

nt>

Title: Need to ensure that the workers of Captive mines owned by TISCO get the benefit of 15 per cent interim relief as per the Coal Wage Board Agreement.

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : सभापति जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय दिया गया है। देश के समस्त कोयला कर्मियों को कैप्टिव माइंस एवं कोल इंडिया के तहत कार्यरत हैं, उनका एक समान वेतन-निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इसके तहत बिन्दु एक से लेकर छः तक के समझौतों का कार्यान्वयन हो गया है। सातवां कोयला वेतन समझौता अभी बाकी है। 15 प्रतिशत इंटरिम रिलीफ देना तय हुआ, जिसके तहत कोल इंडिया की समस्त इकाइयों के मजदूरों को अन्तरिम राहत दी जा चुकी है, परन्तु कैप्टिव माइन्स चलाने वाले टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपने कोयला मजदूरों को 15 प्रतिशत की इंटरिम रिलीफ का भुगतान नहीं किया है और न वह सातवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में भाग ले रहा है।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कोयला-कर्मियों के समान कार्य के लिए एक तरह का वेतन निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं.7 में टिस्को को भाग लेने एवं 15 प्रतिशत इंटरिम रिलीफ का अविलम्ब भुगतान करने का आदेश दिया जाए जिससे मजदूरों को उचित न्याय मिल सके और कोयला खदान के राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing except the written text should go on record.

*(Interruptions)**

* Not recorded